नईदुनिया

अमेरिका को कनाडा का जवाब, 8 सितंबर से कई उत्पादों पर लगाएगा जवाबी टैरिफ

ओटावा

अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए 50 प्रतिशत टैरिफ के जवाब में अमेरिका से आयात होने वाले कई उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने का ऐलान किया है। ये नए टैरिफ 08 सितंबर से लागू किए जाएंगे।

कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिकी शुल्क का जवाब लगभग डालर के बदले डालर के आधार पर देगा, ताकि देश के श्रमिकों, किसानों, परिवारों और कारोबारों के हितों की रक्षा की जा सके।

कनाडा की ओर से स्टील, डेयरी उत्पाद, घरेलू उपकरण, कृषि मशीनरी, पल्प एवं पेपर और इलेक्ट्रानिक्स समेत कई अमेरिकी क्षेत्रों को जवाबी टैरिफ के दायरे में लाने की तैयारी है।

दोनों देशों के बीच कई दिनों तक चली गहन व्यापार वार्ता 21 अगस्त को किसी समझौते के बिना समाप्त हो गई। कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए अमेरिका की अंतिम समय की नई शर्तों को जिम्मेदार ठहराया। उनके अनुसार, ये शर्तें आर्थिक रूप से अनुचित थीं और कनाडा के लिए संभावित समझौते के लाभ को कमजोर कर रही थीं।

अमेरिका के नए शुल्क का असर कनाडा के शराब, फर्नीचर, डेयरी, सीमेंट, कपड़ा, मछली पकड़ने के उपकरण और हाकी से जुड़े सामान समेत कई क्षेत्रों पर पड़ने की आशंका है। रिपोर्टों के अनुसार, नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले निर्यात का करीब पांच प्रतिशत प्रभावित हो सकता है।

कनाडाई सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि अमेरिकी शुल्क से प्रभावित घरेलू उद्योगों के लिए जल्द राहत और सहायता उपायों की घोषणा की जाएगी। वहीं, कुछ व्यापार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते टैरिफ से दोनों देशों के कारोबार, रोजगार और कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।

ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कार्नी के फैसले का समर्थन करते हुए प्रस्तावित व्यापार समझौते को कनाडा के हितों के खिलाफ बताया। दूसरी ओर, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जमीसन ग्रीर ने कहा कि फिलहाल कनाडा के साथ नई व्यापार वार्ता की कोई योजना नहीं है।

न्यूज ब्रीफ

नेपाल ने नहीं मानी मस्क की शर्त, स्टारलिंक को शत प्रतिशत हिस्सेदारी देने से इनकार

काठमांडू। नेपाल ने अमेरिकी कंपनी स्टारलिंक को शत प्रतिशत स्वामित्व देने से इनकार कर दिया है। स्टारलिंक दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क की कंपनी है। नेपाल ने अपनी नई दूरसंचार नीति के हत 20 प्रतिशत स्थानीय साझेदारी के साथ विदेशी निवेश की शर्त रखी है। सरकार की इस शर्त ने स्टारलिंक को नेपाल में अपनी सेवा विस्तार के लिए फिलहाल रोक दिया है। नेपाल में 100 प्रतिशत स्वामित्व की शर्त के बीच विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी कंपनी को देश में लाकर डिजिटलीकरण का विस्तार करने का प्रयास तत्काल सफल होता नहीं दिख रहा है। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी सीमित रखने के लिए अनिवार्य स्थानीय साझेदार की पुरानी व्यवस्था पर कायम है। हाल ही में दूरसंचार नीति के मसौदे में दूरसंचार सेवा संचालित करने के इच्छुक विदेशी निवेशकों के लिए स्थानीय साझेदार को अनिवार्य रूप से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी देने की पुरानी नीति को ही निरंतरता दी गई है।

दहशत में मुनीर ने रावलपिंडी को बना दिया छावनी, इमरान खान विवाद से पाकिस्तान की बढ़ी टेंशन

इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकार ने पंजाब गृह विभाग की सिफारिश पर रावलपिंडी शहर में अगले छह महीनों के लिए सेना तैनात करने की मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण फैसला संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और किसी भी संभावित अप्रिय घटना से प्रभावी ढंग से निपटना है। गृह एवं मादक द्रव्य नियंत्रण मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पाकिस्तान सेना की तीन कंपनियों को रावलपिंडी में संवेदनशील सुरक्षा कर्तव्यों के लिए तैनात किया गया है, जो शहर की सुरक्षा चुनौतियों को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर भयंकर डरे हुए है और वे कोई जोखिम लेना नहीं चाहते। सेना की तैनाती की तत्काल आवश्यकता तब पड़ी जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से कथित तौर पर जुड़े एक व्यक्ति ने रावलपिंडी में सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में वह हमलावर मारा गया। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक हमलावर खैबर जिले का निवासी था और पीटीआई का एक सक्रिय कार्यकर्ता था। उसके पास से पार्टी का झंडा, हथियार और गोलियां भी बरामद हुई थीं। हालांकि, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस घटना से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि उनका आतंकवाद से कोई लेना-देना नहीं है और सरकार जानबूझकर उन्हें इस हमले से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो कि राजनीतिक प्रतिशोध का एक हिस्सा है।

पाकिस्तान में बैठ नेटवर्क चला रहा भारत का दुश्मन शहजाद भट्टी, रचता है साजिशें

इस्लामाबाद। 16 मार्च 2025 की बात है, सुबह के 4 बज रहे थे। पंजाब के जालंधर में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर नवदीप सिंह संधू के घर पर हमला हुआ। बालकनी में ग्रेनेड फेंका गया। पंजाब पुलिस और एनआईए ने इस मामले में हार्दिक कंबोज नाम के युवक को पकड़ा। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने ले ली और मामला हाई प्रोफाइल हो गया। ये पहला या अकेला मामला नहीं है। पाकिस्तान में बैठकर शहजाद भारत में कई साजिशें रच चुका है। बता दें 17 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि भारत में शहजाद का नेटवर्क खत्म कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में बैठे भट्टी और उसके गुर्गों का नेटवर्क अब भी गिरफ्त से बाहर है। ऐसे में क्या वह भारत में फिर से अपना नेटवर्क खड़ा कर सकता है। उसके काम करने का तरीका क्या है। अंडरवर्ल्ड डान दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान में बैठकर भारत में हवाला, तस्करी, फिरौती और आर्गनाइज्ड क्राइम का मजबूत नेटवर्क बना रखा था। वहीं शहजाद भट्टी जमीन पर उतरने के बजाय सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं तक पहुंच रहा है। एनआईए और स्पेशल सेल में मौजूद हमारे सोर्स ने बताया कि शहजाद भट्टी नेटवर्क का मुखिया है, जो सीधे आईएसआई के संपर्क में रहता है। उसके तीन वजीर हैं, जो पाकिस्तान और बलूचिस्तान के बड़े गैंगस्टर है। शनि टाइगर जो पाकिस्तान का गैंगस्टर और हथियार सप्लायर, ब्रेनवाश करने में माहिर है।

अमेरिका की अब ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की तैयारी, तेहरान का पड़ोसियों से साथ न देने का आग्रह

तेहरान/वाशिंगटन

होर्मुज जलडमरूमध्य पर वर्चस्व को लेकर अमेरिका और ईरान के खिलाफ छिड़ा युद्ध अब और आक्रामक होने वाला है। अमेरिका की बड़े आर्थिक युद्ध की चेतावनी से ईरान में हाहाकार जरूर मच गया है पर वह झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को आगाह किया है। उसने इन देशों को चेताया कि अगर किसी ने इस मोर्चे पर अमेरिका का साथ दिया तो उसे ईरान का दुश्मन माना जाएगा। ऐसे देशों के खिलाफ दुश्मन की तरह ही कार्रवाई की जाएगी।

अमेरिका सोमवार को बड़े कदमों की घोषणा कर सकता है। वित्त सचिव स्काट बेसेंट अमेरिका की योजना का खुलासा करेंगे। इस साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हवाई हमले शुरू करने के बाद से लगभग छह महीने की लड़ाई के बावजूद, दोनों पक्ष इस समय एक-दूसरे पर गोलीबारी तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ने के कोई संकेत भी नहीं दे रहे हैं।

होर्मुज में तेल की ढुलाई लगभग ठप हो गई है। तेहरान ने इस अहम जलमार्ग से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी अनधिकृत तेल टैंकर पर हमला करने की धमकी दी है। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों की वजह से भारी दबाव में है। अमेरिकी वित्त सचिव स्काट बेसेंट सोमवार को एक प्रेस कान्फ्रेंस में ईरान पर इतिहास की सबसे सख्त पाबंदियां लगाने की घोषणा कर सकते हैं। बेसेंट ने चीन से भी वाशिंगटन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया है। एनालिटिक्स फर्म केप्लर के 2025 के आंकड़ों के अनुसार, चीन , ईरान से निर्यात होने वाले तेल का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा खरीदता है।

अरब न्यूज, द न्यूज और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने पड़ोसी देशों को अमेरिका के आर्थिक युद्ध में शामिल होने के खिलाफ चेतावनी देते हुए तेल मार्गों पर कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कहा कि तेहरान ऐसे देशों को निशाना बनाएगा। रेजाई ने कहा कि ईरान उन देशों को भी जवाब देगा जिन्होंने अमेरिका को देश पर आर्थिक युद्ध थोपने में मदद की।

रेजाई की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सबसे कड़ी आर्थिक कार्रवाई की योजना की घोषणा के बाद आई है। ट्रंप ने तेहरान को वित्तीय या अन्य सहायता देने वाले देशों को भी गंभीर आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी दी है।

सरकारी प्रसारक आईआरआईबी को दिए साक्षात्कार में कहा कि हमारे सभी पड़ोसी अमेरिका के साथ आर्थिक युद्ध में शामिल न हों, वरना हम उन्हें दुश्मन मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पड़ोसी देशों ने सलाह नहीं मानी तो ईरान फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल निर्यात रोक सकता है। उन्होंने कहा कि तेल की एक भी बूंद बाहर नहीं जाने दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में कहा कि नए प्रतिबंधों में ईरान की आर्थिक जीवनरेखा माने जाने वाली सुविधाओं (तेल तस्करी नेटवर्क, वित्तीय हस्तांतरण, एक्सचेंज हाउस, जहाज पंजीकरण और फ्रंट कंपनियों) को निशाना बनाया जाएगा।

ट्रंप ने कहा, यह एक इकोनामिक डी-डे होगा। ईरान को अलग-थलग करने और हराने के लिए हमें अपने सभी सहयोगियों की जरूरत है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खड़े हों। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु शक्ति बनने का सपना त्यागना होगा। हथियार नहीं रखने दिया जाएगा। इस पर रेजाई ने कहा कि ट्रंप ने वैश्विक परमाणु सुरक्षा को मजबूत करने के बजाय परमाणु असुरक्षा पैदा कर दी है। उन्होंने दावा किया कि तेहरान के खिलाफ वाशिंगटन के कदमों से देशों की परमाणु हथियार हासिल करने में दिलचस्पी बढ़ी है।

ईरान के उपराष्ट्रपति (प्रथम) मोहम्मद रजा अरेफ ने ट्रंप के आर्थिक युद्ध शुरू करने की धमकी देने की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंध ईरानी लोगों के संकल्प को नहीं बदल पाएंगे। ईरान के विदेशमंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भी ट्रंप की इसके लिए आलोचना की है।

इस बीच बाल्कन देश बुल्गारिया ने कहा कि ईरान की नाराजगी के बीच दो अमेरिकी टैंकर विमान ((केसी-135) बुल्गारिया से रवाना हो गए हैं। बुल्गारिया के रक्षामंत्री दिमितार स्टोयानोव ने बताया कि दो अमेरिकी टैंकर विमान बुल्गारिया के बेजमर एयरबेस से रवाना हो गए हैं।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका की आसन्न घोषणा संयुक्त राष्ट्र के हर स्वतंत्र सदस्य देश पर अतिरिक्त क्षेत्रीय संप्रभुता थोपने जैसा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अंतरराष्ट्रीय कानून में ऐसी सेकेंडरी पाबंदियों का कोई आधार नहीं है। इससे पहले ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ आफ स्टाफ, मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरान दुश्मन की धमकियों का सैन्य रूप से करारा, दंडात्मक और विनाशकारी जवाब देगा।

जापान में आधी रात को कांपी धरती, दहशत में घरों से भागे लोग

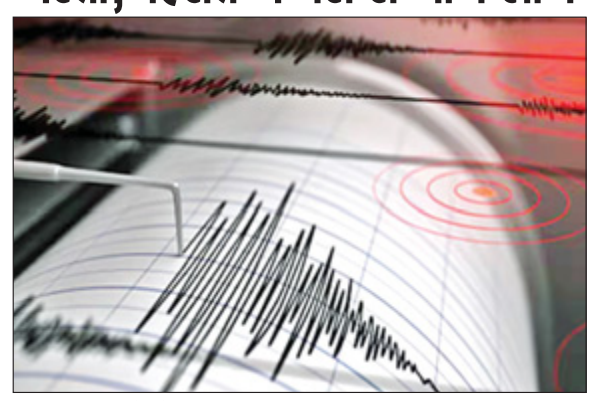

टोक्यो

जापान में 5.9 तीव्रता के भूकंप से कई इलाके दहल उठे। जब लोग गहरी नींद में थे, तभी खिड़कियां और दरवाजे जोर-जोर से हिलने लगे और घरों में रखी चीजें गिरने लगीं। अचानक आए तेज झटकों से घबराए लोग बच्चों और बुजुर्गों को लेकर घरों से बाहर निकलकर सड़कों और खुले स्थानों की ओर भागे। भूकंप का केंद्र दक्षिणी इबारकी प्रांत में जमीन से करीब 70 किलोमीटर नीचे बताया गया।

इबारकी के अलावा टोक्यो, साइतामा और चिबा में भी तेज झटके महसूस किए गए। जापान के सात-बिंदु वाले भूकंपीय पैमाने पर इसकी तीव्रता लोअर 5 दर्ज की गई। इस स्तर के झटकों में मकानों की दीवारों में दरारें आने और बिना सहारे रखी भारी वस्तुओं के गिरने का खतरा रहता है। राहत की बात यह रही कि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई।

पुराने जख्मों ने बढ़ाई दहशत

नए भूकंप के झटकों ने जापान के लोगों के हालिया त्रासदी के जख्म फिर ताजा कर दिए। कुछ सप्ताह पहले क्यूशू के कुमामोटो इलाके में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। उस

खिड़की दरवाजों से आई डराने वाली आवाज

हादसे में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 62 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कई घायलों की हालत गंभीर बताई गई थी। बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान पहुंचा था, जिससे स्थानीय लोगों में भूकंप का डर अभी भी बना हुआ है।

माल हादसे की याद से सहमे लोग

पिछले विनाशकारी भूकंप के दौरान काशिमा शहर के एक बड़े माल में भी भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। झटकों के बीच करीब 3,000 लोगों को पार्किंग क्षेत्र में सुरक्षित निकाला गया था। इसके बाद माल के एक हिस्से में गैस विस्फोट हुआ, जिससे दूसरी मंजिल का बड़ा हिस्सा ढह गया।

मलबे में कई लोग फंस गए थे और राहत एवं बचाव दल ने भारी उपकरणों और क्रेन की मदद से कई दिनों तक अभियान चलाया था। नए झटकों ने लोगों को एक बार फिर उसी भयावह दौर की याद दिला दी। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की तत्काल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भूकंप के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।

पाक के बलोचिस्तान के कोयला खदान में जहरीली गैस की चपेट में आए दो खनिकों की मौत

इस्लामाबाद (पाकिस्तान)। देश के बलोचिस्तान प्रांत की डुकी कोयला खदान में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो खनिकों की मौत हो गई और चार बेहोश हो गए। बचाव दल ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले जुलाई आखिर में क्वेटा के बाहरी इलाके में धमाके से कोयला की एक खदान ढहने से 34 खनिकों की मौत हो चुकी है। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शवों और बेहोश मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया। बचाव दल के सूत्रों ने बताया कि कोयला खदान लंबे समय से बंद थी। इससे उसमें जहरीली गैस भर गई। खदान में पहुंचते ही इसी गैस के कारण खनिकों की मौत हो गई। इससे पहले 30 जुलाई को बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में कोयला खदान गैस धमाके से ढह गई थी। इस हादसे में 34 खनिकों की मौत हो गई। यह हादसा क्वेटा के सोरेंज इलाके की कोयला खदान में हुआ था।धमाके के समय 42 कर्मचारी काम कर रहे थे। बाकी खनिकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।

अतीत को समझने की प्रक्रिया वर्तमान के ज्ञान से होती है प्रभावित: फार्समैन

केप टाउन

दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, लेसोथो और मोजाम्बिक में लंबे समय तक शोध करने वाले पुरातत्वविद् टिम फार्समैन का मानना है कि अतीत को समझने की प्रक्रिया हमेशा वर्तमान के ज्ञान, परिस्थितियों और दृष्टिकोण से प्रभावित होती है। इतिहास केवल बीते समय का रिकार्ड नहीं होता, बल्कि उसे समझने का हमारा नजरिया भी समय के साथ बदलता रहता है। विज्ञान, तकनीक, राजनीति और सामाजिक परिस्थितियों में बदलाव आने के साथ अतीत की व्याख्या भी नई दिशा लेती है। अपनी पुस्तक में उन्होंने अफ्रीका में पुरातत्व के विकास को चार प्रमुख चरणों में विभाजित किया है। इनमें शुरुआती दौर, पुरातत्व का व्यवस्थित विकास, परिपक्वता का चरण और पूरे महाद्वीप में इसके विस्तार का काल शामिल है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन चरणों की सीमाएं पूरी तरह निश्चित नहीं हैं और समय के साथ इनमें कई बदलाव देखने को मिले। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, जब यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित कर रही थीं, उस समय पुरातत्व का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह करना था। उस दौर में खोजी गई सामग्री का वैज्ञानिक विश्लेषण बहुत कम किया जाता था।

संग्रहालयों के कर्मचारी, मिशनरी, प्रशासक और यात्री ही अधिकतर अनुसंधान कार्य करते थे, जबकि प्रशिक्षित पुरातत्वविदों की भूमिका सीमित थी। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में पुरातात्विक अनुसंधान अधिक वैज्ञानिक और व्यवस्थित हुआ। 1920 के दशक तक विश्लेषण आधारित नई शोध पद्धतियां विकसित हो चुकी थीं। इसके बावजूद लंबे समय तक अफ्रीका के इतिहास को औपनिवेशिक सोच के प्रभाव में देखा जाता रहा। कई मिथक और गलत धारणाएं, जैसे बाहरी सभ्यताओं द्वारा अफ्रीका के विकास की अवधारणा, शोध पर हावी रहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विज्ञान और तकनीक में हुई प्रगति ने पुरातत्व को नई दिशा दी। रेडियोकार्बन डेटिंग जैसी

आधुनिक तकनीकों ने पुरातात्विक खोजों की आयु का अधिक सटीक निर्धारण संभव बनाया। इससे इतिहास की कई पुरानी धारणाओं का पुनर्मूल्यांकन हुआ और अफ्रीकी सभ्यताओं के विकास को नए दृष्टिकोण से समझा जाने लगा।

1960 के दशक के बाद स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी पुरातत्व अनुसंधान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। लोग केवल श्रमिक के रूप में ही नहीं, बल्कि अपने पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय इतिहास के माध्यम से भी शोध प्रक्रिया में शामिल होने लगे। स्वाहिली तट इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है, जहां पहले बाहरी प्रभावों पर अधिक जोर दिया जाता था, लेकिन बाद के अध्ययनों ने स्थानीय समाज की ऐतिहासिक भूमिका को प्रमुखता दी। विशेषज्ञों का मानना है कि पुरातत्व केवल प्राचीन वस्तुओं की खोज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति और सभ्यताओं के विकास को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

पाकिस्तान ने पीओके को नर्क बना दिया, यूएन से हस्तक्षेप की मांग

ब्रिटेन के सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र को लिखा पत्र

लंदन

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में बिगड़ते हालात को लेकर 70 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही पाकिस्तानी बलों द्वारा किए जा रहे नरसंहार को खत्म करने और नागरिकों की जान की सुरक्षा के उपाय करने की अपील भी की गई है। यह पत्र पीओके में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन और नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों की ओर वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता है।

ब्रिटिश सांसदों की अपील क्षेत्र में बढ़ती हिंसा और दुर्व्यवहार के बीच आई है, जहां पाकिस्तानी बलों की क्रूर कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। क्षेत्र में अभी भी सख्त नाकाबंदी, कर्फ्यू और पूरी तरह से कम्युनिकेशन्स ब्लैकआउट लागू है, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित पत्र में ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में, मौतों, संचार पर प्रतिबंधों, मनमानी गिरफ्तारियों, आवश्यक आपूर्ति में व्यवधान और शांतिपूर्ण नागरिक और राजनीतिक अभिव्यक्ति पर लगाम की रिपोर्टों ने काफी चिंता पैदा की है। हमने ब्रिटिश कश्मीरियों से भी लगातार सुना है, जो संबंधित क्षेत्र में अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता में हैं। यह स्थिति मानवीय संकट का रूप लेती जा रही है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने पीओके में पाकिस्तान की बर्बरता को लेकर आवाज उठाई थी और कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान इस तरह का अत्याचार करने को लेकर पाकिस्तानी सरकार को जवाब देना चाहिए। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कार्रवाई पर बढ़ती चिंता को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पीओके के हालिया घटनाक्रम पर चिंता जताई थी।

उन्होंने प्रदर्शनकारियों की मौत मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराए जाने तथा पाकिस्तान द्वारा संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति पर प्रतिबंध लगाने एवं उसके नेताओं को गिरफ्तार किए जाने का मुद्दा उठाया था।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने के अधिकार का उल्लंघन करते हुए इंटरनेट के इस्तेमाल और सार्वजनिक सभाओं पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर भी चिंता जताई गई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अशांति के कारण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के सदस्यों की हुई सभी मौतों की गहन और निष्पक्ष जांच तत्काल कराए जाने का आह्वान किया था। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति (जेएएसी) ने इन प्रदर्शनों की अगुवाई की। इनमें ट्रांसपोर्टर, छात्र, वकील, कार्यकर्ता एवं अन्य लोग शामिल हैं।